BROADCASTING, AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the capital of Gujarat State with the population of nearly 1,50,000 persons, is in advance stage of construction and Government's offices and Sachivalaya are to be shifted in June 1970, and the new capital is required to be included in Ahmedabad local area for the purpose of Calls between Gandhinagar and Ahmedabad so as ato void trunk dialling between them ;

(b) whether Government are thinking to link Gandhinagar with New Delhi, Bombay, Baroda and other important cities in the country on the S.T.D. system to which Ahmedabad is now linked ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) The State Government had intimated that the State Government Offices and Sachivalaya are proposed to be shifted to Gandhinagar progressively during 1970. They had also suggested that Gandhinagar be included in the local area of the Ahmedabad Telephone System for purposes of calls between Gandhinagar and Ahmedabad.

It has, however, not been possible to accept this suggestion of the economics of providing the telephone services between exchanges suited for apart and our experience in the working of similar cases in the past. However, adequate local and trunk telecommunication facilities are being provided at Gandhi Nagar. It is also proposed to link Gandhi Nagar and Ahmedabad on Subscriber Trunk Dialling basis, with metering every 36 seconds during the day and 72 seconds during the night.

(b) Yes, Sir. Plans are being drawn up as in case of all other State capitals.

(c) Does not arise.

Re : POLITICAL DEVELOPMENTS IN PUNJAB

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी आप कम्बोडिया के बारे में कालिंग एटेन्शन नोटिस ले रहे हैं । क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम कंम्बोडिया के बजाये पंजाब की चर्चा करें ? कम्बोडिया तो बहुत दूर है । पंजाब हमारे देश में ही है ।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : The Punjab matter is very important. Under inspiration from here Shri Gurnam Singh has been asked to from the Government despite the fact that his motion was rejected on the floor of the House.... (*Interruption*)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी आप के सचिवालय ने हमें यह सूचना दी है कि पंजाब के सम्बन्ध में हमने जो ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव का नोटिस दिया था, उसको आपने स्वीकार नहीं किया है । आप यह मानेंगे कि पंजाब में एक गम्भीर सांविधानिक स्थिति पैदा हो गई है । मुख्य मंत्री ने विधान सभा का विश्वास खो दिया । लेकिन राज्यपाल ने उनसे त्यागपत्र नहीं मांगा । (व्यवधान) पहले नहीं मांगा । रात भर ...(व्यवधान)

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : He has resigned already.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरा सवाल यह है कि पंजाब में बहुमत किस का है और किसे सरकार बनाने के लिए बुलाया जाये, आखिर राज्यपाल किस कसौटी पर यह निर्णय करेंगे । मुझे शक है कि केन्द्रीय सरकार पंजाब के मामले में ऐसा हस्तक्षेप करेगी, जिस से संविधान की अवहेलना होगी । आप गृह मंत्री को कहिये कि वह इस सम्बन्ध में सदन को विश्वास में लें और पंजाब की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दें और हमें उस पर चर्चा कराने का अवसर दिया जाये । (व्यवधान)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज पंजाब एसेम्बली में मार-पीट हुई है।(व्यवधान)

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Mr. Speaker, I am glad that you allowed Shri Atal Bihari Vajpayee to speak. Kindly extend the same facility to others. You have, of course, been pleased to disallow the calling-attention. I do not challenge your ruling. Nonetheless, we wrote to you to allow us to speak briefly about this.

Sir, we do not take any pleasure in trying to raise these issue but we do not creat these issues. Shri Gurnam Singh does not sit herr; he sits there. What has happened in that House becomes a concern for this House. The issue is very simple. The Chief Minister was defeated on the floor of the Hause. There is a constitutional propriety which calls for the attention of this House and we cannot ignore our duty. We find that here is a man who has been defeated on the floor of the House, has been disowned by his party and has been asked by the Governor to resign. We now find that the same man continued since yesterday till this morning. Yesterday, he suggested that the Assembly should be dissolved. Later on, he said, he can form a Ministry.

I want to raise a point of constitutional propriety. Under aricle 164(2), the duty is very clear. It says :

> "The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State."

The moment that confidence of the Assembly is lost, the first thing that any Chief Minister has to do is to tender his resignation. That is incumbent on him. Mr. Gurnam Singh ought to have resigned yesterday even before waiting for dismissal by his own party. Sir, the other day, you were good enough to tell us that during the 3 hours' debate on Haryana you learnt what you did not learn in 10 years. I do not want to take it literally. That showed your ganerosity. You emphassed the vital issues involved.

These are the vital issues. The Parliament is the only forum where we can ensure that constitutsonal safeguard and properiety are upheld. We do not want to arrogate to ourselves the right of the State Assembly But the Parliament has the duty and that duty is to ensure that the sanctity of the Constitution is upheld in every State. Yesterday, that sanctivity was in danger. If we do not do our duty here, in this House, I do not know what will be happening in Punjab.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

SHRI H.N. MUKERJEE (Calcutta North East) : Are we to disturb the rules, the procedure, of the Honse like this ?

MR. SPEAKER : I have already disallowed it.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : This morning, I gave a Call Attention notice about the pro-Mao red flag on the Tezpur court building. You have disallowed it.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आप हमारी बात भी सुन लीजिये। जब दो सदस्यों को आप ने सुना है हम लोगों की भी सुन लीजिए । मैं ज्यादा समय आप का नहीं लेना चाहता।... (व्यवधान) या तो इस पर बहस होने ही नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जब आप ने औरों का है तो हमारी बात भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस में एक बात यह बड़ी गलत है कि जो बात आप मुझ से मेरे चैम्बर में कर सकते हैं वह वहां तो करते नहीं हैं और यहां आकर मुझ को फोर्स करते हैं और कहते सुना हैं कि यह कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट है...

श्री मधु लिमये : यह चैम्बर की बात नहीं है। यहीं इसी जगह पर इस के ऊपर निर्णय देना होता है। आप हमारी बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हमने जो अभी थोड़े अरसे से यह रोल अख्त्यार कर लिया है कि स्टेट में जो बात आए उसके ऊपर हमें यहां बहस करनी है और पार्लियामेंट को इतने अख्त्यार देने शुरू

कर दिये हैं, मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है अगर कोई कांस्टीट्यूशनल क्राइसेस है, कोई आदमी चल रहा है, उस का रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन आज सुबह चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया और विधान सभा स्थगित हो गई ।...

श्री मधु लिमये : कल क्यों नहीं दिवा ?

अध्यक्ष महोदय : जो चीज विधान सभा को करनी हैं वह हमीं करना शुरू कर दें तो कहां इस का अंजाम होगा ?

डा० राम सुभग सिंह : यहां से कहा गया था उनको कि आप मत रिजाइन कीजिए और कांग्रेस पार्टी ने वहां उन को रिपोर्ट किया, तो यह गलत काम इन्होंने किया जिस की बिना पर उन्होंने भी गलत काम वहां किया ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है । कोई कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट है तो आप कह सकते हैं । क्या कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट है ?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 164 में दो बातें बिलकुल साफ हैं कि सरकार का उत्तरदायित्व विधान सभा के प्रति है और मुख्य मंत्री अगर विधान सभा का विश्वास खो देता है तो उस को एक सेकेंड भी मुख्य मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं हैं । इस के बारे में जो परिपाटी है और संविधान के नियम हैं उसके ऊपर में कुछ बातें पेश करना चाहता हूं । इन दिनों में यह बहुमत वाली सरकारें कम रह गई हैं यानी एक दल का बहुमत जहां हो ऐसी बहुत कम जगहें हैं, तो इसलिए इन परिपाटियों पर अमल करना बहुत जरूरी है । मैं आप के सामने इंगलैंड की दो मिसालें रखना चाहता हूं । लार्ड साल्सबरी ने पिछली शताब्दी में रैडल्फ चर्चिल को जो कहा था वह मैं रख रहा हूं...(**व्यवधान**)

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : As per order paper, the Calling Attention motion has to be taken up. Why are you allowing discussion on this (*Interruption*)

SHRI S. KUNDU (Balasore) : You are prepared to listen to constitutional points but you are not allowing a call attention motion. You try to understand us, Sir.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अभी आप ने फरमाया कि संवैधानिक बातें आप कर सकते हैं तो मैं संविधान की ही बातें रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट बताइए, लम्बे चौड़े भाषण में मत जाइए ।

श्री मधु लिमये : तो फिर यह हल्ला क्यों मचाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता ।

मैं यह अर्ज करना चाहता था कि इंगलैंड में यह परिपाटी बनी है कि किन सवालों को ले कर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए और किन सवालों पर हारने के बाद इस्तीफे की जरूरत नहीं है । इस के बारे में मैं अर्ज कर रहा था । अगर साल्सबरी की बात को छोड़ देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए । रैमजे मैकडोनल्ड ने जब वहां 1924 में अल्पमत की सरकार बनाई तो उस समय घोषणा की थी कि :

> "The Labour Government will go out if it is defeated upon substantial issue, issues of principles and issues which really matter."

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद... (**व्यवधान**)... यह बीच में क्यों टोक रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

SHRI H.N. MUKERJEE : We must follow a certain procedure. Before calling attention matter is taken up, you allow constitutional matters. This 'punditry' should stop.

श्री मधु लिमये : मेरे लिये ही क्यों यह प्रतिबन्ध है ? अब तक दो सदस्य बोल चुके हैं।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : दो बोले वह भी गलत बोले और यह भी गलत बोल रहे हैं। एक गलत बात हो गई तो उसको अपनी गलती से यह ठीक कर रहे हैं।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह है कि जिस बात को लेकर मंत्रि-मंडल की वहां पराजय हुई और वह बुनियादी बात है या नहीं ? अगर मामूली बात कोई होती और उसके ऊपर पराजय होती... (**व्यवधान**) एस. एस. पी. का इस में सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह मामला मामूली नहीं था। इस के बारे में आइवर जैनिग्स ने कहा है, वह मैं पढ़ रहा हूं :

> "The House whose opinion was rejected has always the ultimate remedy of the refusal of supply."

अब अप्रोप्रिएशन बिल पर जब वह पराजित हो जाते हैं तो एक सेकेंड भी उनको नहीं रहना चाहिए था और गवर्नर को चाहिए था कि जब इस्तीफा देने के लिए कल तैयार नहीं थे तो उन को वह हटा देते। अगर इस तरह मनमानी चलेगी तो देश में संसदीय प्रणाली चल नहीं सकती है, लोकतंत्र खत्म हो जायगा। इस बात को हम सदन के सामने रखना चाहते हैं। तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस का कोई मतलब नहीं है। कल से आज सवेरे तक उन्होंने अप्रो-प्रिएशन बिल पर हारने के बाद भी क्यों इस्तीफा नहीं दिया, इसका संतोषजनक उत्तर हमें मिलना चाहिए।

SHRI SURENDRANATH DIWIVEDY (Kendrapara) : As mentioned by Mr. Mukerjee, when you have allowed a discussion, when you have allowed constitutional points being raised, we would like to know from you after hearing the constitutional points as to what is your decision. Are you allowing the call attention notice or are you allowing a discussion ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री(हापुड़): अध्यक्ष महोदय, अगर आप सुनें तो मेरा निवेदन एक यह है कि हमारी बड़ी दिक्कत यह है कि हम आप से अनुमति लिए बिना बोलना प्रारंभ नहीं करते हैं। अब इस प्रकार की इजाजत अगर दें आप कि आप इजाजत दें या न दें जो चाहे बोलने लगे तो हम भी उसको अपना लें।

मुझे एक बात जो कहनी थी वह यह कि आप की ही गद्दी पर बैठे हुए जो आपसे पुराने अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में सभी राज्यों के विधान मंडलों के अध्यक्ष पीछे एकत्रित हुए थे उन्होंने मिल कर यह निर्णय किया था कि राज्य में किसी पार्टी का बहुमत है या नहीं, विधान सभा के अन्दर इस की परीक्षा की जाएगी। विधान सभा के अन्दर कोई सत्तारूढ़ पार्टी अगर अपना बहुमत खो बैठती है तो स्वाभाविक है कि उस को त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने वहां त्यागपत्र नहीं दिया। आज प्रातःकाल उनका त्यागपत्र आया। गृह मंत्री यहां मौजूद हैं, इस बारे में जो तरह-तरह की शंकाएं बढ़ रही हैं उसके सम्बन्ध में जो जानकारी उन के पास है उसके ऊपर एक वक्तव्य वह सदन में दें। वह जानकारी वह सदन को भी दें और देश को भी दें। क्योंकि यह जो राजनैतिक परिवर्तन देश में हो रहे हैं इन परिवर्तनों में कहीं हम ऐसी गलत परम्पराओं को प्रारम्भ न कर दें कि बाद में जाकर उन्हें संभालना कठिन हो जाय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सदन में दें ताकि सदन को और देश को भी सही जानकारी हो सके।

SHRI S KUNDU : When I gave the call attention notice, I had only one thing in my mind. I just wanted to know whether Mr. Gurnam Singh has resigned and whether he advised the Governor to dissolve the Assembly. The point arises whether a defeated Chief Minister can advise that thing. The Governor telephoned here and the Home Minister advised him 'You cannot accept the advice'. This is a very important thing. The Chief Minister said : 'I have been defeated so that you should dissolve the assembly' and then he says this that this is not actually a defeat now and all that. This is an important constitutional matter. The country is very much concerned with it.

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : You have called me. For the last one month I have been inviting your attention. Today I will not yield for anyone except you, Sir. For one month I have been waiting.

SHRI S. KUNDU : Government should make a statement.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : You don't allow us, Sir. Why this discrimination ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAVEE : You may kindly allow her Sir.

SHRI M.L. SONDHI: I have a point of order. You have called me, and Sir, am I supposed to have super-human patience ?

MR. SPEAKER : I have just accepted the request from your leader. I am not super-human.

SHRI M.L. SONDHI : You are superhuman.

MR. SPEAKER : I have just accepted a very kindly word from your leader.

DR. SUSHILA NAYAR : May I ask this from the Government through you, Sir ? After the defeat on the floor of the House Mr. Gurnam Singh is supposed to have said that he is still enjoying the majority and he is trying to form Government with the collaboration of other parties. How can he say that ? Is that consistent with the Constitution ? We would like to know that from you. We would like to have your opinion on this matter. How can he say he has got majority and how can the Governor give him another chance without giving a chance to Mr. Bidai ? We would like to know your opinion about this codstitutional procedure.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: Ask the Home Minister to make a statement. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : Order please.

SHRI HEM BARUA : The Home Minister should make a statement. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : Yesterday this news came that he was defeated. Then I had another news that he was advising.... (*Interruption*)

AN HON. MEMBER : We want your ruling. (*Interruption*)

MR. SPEAKER : You want my ruling, abruptly, like this ? I just want to tell you, he issued another statement that he was advising the Governor for dissolution, etc. And after this when the Assembly was adjourned he said, he will continue as Chief Minister and there and then मेरा माथा ठनका, आप लोग पहले ही बहुत मेहरबान है, मेरे लिय तो और मश्किल हो जायगी Then situation changed from one position to the other and the same thing has happened. The whole thing is out of joint; and I don't know what is going on. So much abnormality,—everything is so abnormal these days,—and now the only position is this. Now, when he has resigned, the only task that you want to perform is to have an academic discussion. (*Interruption*) If he had not resigned...

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आगे को बुलाया जायेगा यह महत्वपूर्ण सवाल है। गवर्नर ने कहा है कि वह वाच कर रहे हैं। क्या गुजराल साहब की वजह से उन्होंने ऐसा कहा है, हमें सही बात मालूम होनी चाहिये। यह गवर्नर की मिसचिफ है।

MR. SPEAKER : If be had not resigned, it would have been a different matter, and a constitutional issue would have arisen but he resigned within 24 hours. If bon. Members want to have an academic discussion, that is a different matter...

श्री मधु लिमये : इस तरह की बात न हो, इस लिए यह जरूरी है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप किसी भी फौर्म में रखिये लेकिन यहां डिस्कशन होना चाहिये।

MR. SPEAKER : I am considering it, and I shall be asking the Home Minister to make a statement.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Shri I. K. Gujaral was responsible for the fall of the Punjab Government. As soon as he got elected, he stopped the Government there.

MR. SPEAKER : I shall be asking the Home Minister to make a statement.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: When will he be making the statement?

MR. SPEAKER : As soon as possible.

SHRI S. KUNDU : He may make it in the course of the day.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Home Minister is ready to make the statement just now. Let him make it.

MR. SPEAKER : Let the next item be over. Then, I shall see to it. Why should hon. Members not allow the business to go on item-wise ?

12.47 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DEVELOPMENTS IN CAMBODIA

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

> "The reported recent developments in Cambodia and the role of India as Chairman of International Control Commission."

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH) : The Government of India have been watching with great concern the recent developments in Cambodia. The House will recall the press reports indicating that demonstrations took place in Phnompenh on 11th March, 1970 directed mainly against the Embassies of the Democratic Republic of Vietnam and the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam. The demonstrators objected to the presence in the Combodian territory of forces of DRBN and PRG. This was followed by a resolution adopted unanimously at the joint session of the National Assembly and the Council of Kingdom of Cambodia expressing support for the demands of the demonstrators that Government take urgent and timely measures to defend the territorial integrity of the country.

It has been further reported that on 18th March the Cambodian Parliament adopted a motion deposing Prince Norodom Sihanouk as the Head of the State of Cambodia and electing Mr. Cheng Heng, Speaker of the National Assembly, as the Acting Chief of State till the election of a new Head of State is held. It has also been announced that Cambodia will continue to pursue a policy of independence, sovereignty, peace, strict nentrality and territorial integrity and that there has been no change in the Constitution of the Kingdom. It has also been reaffirmed that Cambodia will continue to respect all previous commitments, treaties and conventions signed between Cambodia and all friendly countries as well as all international agencies.

From the reports we learn further that Prince Norodom Sihanouk who is now in Peking has declared that the action of the Cambodian Parliament to depose him is unconstitutional and that he can be deposed only by a national refrendum. There are